भोपाल, शुक्रवार
04
अप्रैल-2025

दैनिक
पीपुल्स प्रवक्ता

भोपाल, ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित

/Peoplespravakta

E-paper www.peoplespravakta.com | वर्ष: 08 | अंक : 355 | पृष्ठ : 08 | मूल्य : 02 रूपए | E-mail Peoplespravakta@gmail.com

सुविचार

आश्चर्य का तात्पर्य सीखने की इच्छा से है...

प्रदेश में पीपीपी मोड पर विकसित की जाएंगी नर्सरियां

उद्यानिकी और खाद्य प्र-संस्करण पर केंद्रित वर्कशाप और मेले जिला स्तर पर लगाएः मुख्यमंत्री डॉ. यादव

- इंदौर के मालवी आलू व गराडू तथा जबलपुर के मटर व सिंघाड़ा सहित जिले के उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की प्रकिया जारी
- इन्वेस्टर्स समिट के समान उद्यानिकी व खाद्य प्र-संस्करण पर भी आयोजन हों
- विश्वविद्यालयों व शासकीय विभागों की खाली जमीनों पर उद्यान विकसित किए जाएं
- रोजगारपरक गतिविधियों के लिए खाद्य प्र-संस्करण पर विशेषज्ञता आधारित सेल गठित किया जाए
- चंबल, मालवा और महाकौशल में क्षेत्र विशेष की आवश्यकतानुसार उद्यानिकी विकास की बनाई जाए कार्य योजना
- बागवानी और नर्सरी लगाने को जन आंदोलन बनाना जरूरी
- विधायक और पंचायत प्रतिनिधि अपने -अपने क्षेत्र में विकसित करें आदर्श बागवानी
- उद्यानिकी में नवाचार करने वाले किसानों को किया जाए सम्मानित
- सीएम ने की उद्यानिकी तथा खाद्य संस्करण विभाग की समीक्षा

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में उद्यानिकी फसलों की जिलेवार मैपिंग की जाए। विश्वविद्यालय सहित अन्य शासकीय विभागों की खाली जमीनों पर उद्यान विकसित करने तथा प्रदेश में पीपीपी मोड पर नर्सरीयां विकसित करने के लिए कार्य योजना बनायी जाए। प्रदेश के सभी जिलों में उद्यानिकी और खाद्य प्र-संस्करण पर केंद्रित वर्कशॉप और मेले आयोजित कर जिलों के किसानों और उद्यमियों को अन्य जिलों में संचालित बेस्ट प्रैक्टिसेज से परिचित कराया जाए। जिलों में कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में नवाचार करने तथा अपने स्तर पर इस क्षेत्र में उपलब्धियां अर्जित करने वाले किसानों का सम्मान किया जाए। इन्वेस्टर्स समिट के समान प्रदेश में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण पर समिट का आयोजन हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में उद्यानिकी तथा खाद्य प्र-संस्करण विभाग की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। बैठक में उद्यानिकी तथा खाद्य प्र-संस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश में कृषि विशेष रूप से उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। प्रदेश, भौगोलिक दृष्टि से सम्पन्न है, साथ ही सिंचाई और बिजली की

भी पर्याप्त उपलब्धता है। प्रदेश कि उद्यानिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से भी आगे निकले। उद्यानिकी के साथ खाद्य प्र-संस्करण के माध्यम से रोजगार के अवसर निर्मित करने की दिशा में भी अंन्तर्विभागीय समन्वय के साथ कार्य किया जाए। विभाग में विशेषज्ञों तथा तकनीकी दक्षता पर केंद्रित सेल स्थापित कर खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को प्रोत्साहित किया जाए। प्रदेश के तीनों क्षेत्रों चंबल-मालवा और महाकौशल में उद्यानिकी की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुसार कार्य योजना बनाई जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को उनकी मेहनत और उपज का वाजिब मूल्य मिले, उन्हें यह भरोसा दिलाना आवश्यक है। किसानों की उपज के लिए उपयुक्त सुविधाजनक स्थलों पर स्टोरेज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही आस-पास की मंडियों में उपज के मूल्य की सही जानकारी किसानों को उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था विकसित करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में बागवानी विकसित करने को जन आंदोलन बनाना जरूरी है। सभी विधायक और पंचायत प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र में आदर्श बागवानी या नर्सरी विकसित कर क्षेत्र के किसानों को अपने स्तर पर प्रेरित करें। श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किसानों को पुरस्कृत करने की व्यवस्था भी हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दीनदयाल शोध संस्थान कृषि विज्ञान केंद्र जैसी संस्थाओं से किसानों के संवाद को भी प्रोत्साहित करना आवश्यक है। बैठक में जानकारी दी गई कि आगामी माह में नीमच, मंदसौर में औषधीय कृषि के लिए उद्यानिकी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा। प्रदेश में 22 लाख 72 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में उद्यानिकी फसलें ली जा रही हैं। आगामी 5 वर्ष में 33 लाख 91 हजार हैक्टयर तक ले जाने का लक्ष्य है।

प्रदेश मसालों के उत्पादन में देश में प्रथम, उद्यानिकी में द्वितीय, पुष्प और सब्जी उत्पादन में तृतीय तथा फल उत्पादन में देश में चौथे स्थान पर है। रीवा के सुंदरजा आम और रतलाम के रियावन लहुसन को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से खरगोन की लाल मिर्च, जबलपुर के मटर, बुरहानपुर के केले, सिवनी के सीताफल, बरमान नरसिंहपुर के बैंगन, बैतूल के गजरिया आम, इंदौर के मालवी आलू, रतलाम की बालम ककड़ी, जबलपुर के सिंघाड़ा, धार की खुरासानी इमली और इंदौर के मालवी गराडू को जीआई टैग दिलाने की प्रकिया जारी है। इससे इन उत्पदों के निर्यात में वृद्धि होने से किसानों की आय भी बढ़ेगी। बैठक में विभिन्न केंद्रीय और राजकोषीय योजनाओं की प्रगति की समिक्षा की गई।

राजनाथ सिंह का सेना को साफ संदेश, कहा-

दुश्मनों के प्रॉक्सी वॉर से निपटने के लिए रहे तैयार

नई दिल्ली, एजेंसी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर से पुष्टि की कि भारत का प्रतिद्वंद्वी पश्चिमी सीमाओं पर छद्म युद्ध जारी रखे हुए है, साथ ही उन्होंने सीमा पार आतंकवाद का दृढ़ता से जवाब देने के लिए भारतीय सेना की सराहना की। सेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंह ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से निपटने में सेना और अन्य सुरक्षा बलों के बीच समन्वय की सराहना की। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खतरे से निपटने में सीएपीएफ/पुलिस बलों और सेना के बीच उत्कृष्ट तालमेल की सराहना करता हूं।

केंद्र शासित प्रदेश में समन्वित अभियान क्षेत्र में स्थिरता बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं और इसे जारी रखना चाहिए। रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में

आयोजित सम्मेलन में वरिष्ठ कमांडरों को संबोधित किया, जो 1 से 4 अप्रैल तक चलेगा। वर्ष में दो बार आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सुरक्षा चुनौतियों, सीमा की स्थिति, आंतरिक सुरक्षा और संगठनात्मक परिवर्तनों का आकलन करने के लिए शीर्ष सैन्य नेतृत्व एकत्रित होता है। इसमे आधुनिकीकरण, रसद, प्रशासन और वैश्विक सुरक्षा विकास के प्रभाव पर भी चर्चा की गई। सिंह ने देश के सबसे भरोसेमंद संस्थानों में से एक के रूप में भारतीय सेना की भूमिका पर जोर दिया और सीमाओं की सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने और नागरिक अधिकारियों की सहायता करने में इसके प्रयासों की सराहना की।

40 साल बाद कोई भारतीय एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएगा

नई दिल्ली। इस मिशन में पैगी व्हिटसन कमांडर होंगी। वहीं शुभांशु शुक्ला पायलट होंगे। स्लावोस्ज़ और टिबोर कापू मिशन विशेषज्ञ होंगे। इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एक्सिओम मिशन 4 के तहत मई में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा सकते हैं। इस मिशन में चार देशों के चार एस्ट्रोनॉट 14 दिन के लिए स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एक अपडेट में इसकी जानकारी दी। नासा और इसरो के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया है। अभी वह इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर है। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। इससे पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। चार देशों के चार एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन जाएंगे। एक्सिओम 4 मिशन के चालक दल में भारत, पोलैंड और हंगरी के मेंबर शामिल हैं। शुभांशु शुक्ला 1984 के बाद से अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे एस्ट्रोनॉट होंगे। स्लावोज़ उज़्नान्स्की 1978 के बाद स्पेस में जाने वाले पोलैंड के दूसरे एस्ट्रोनॉट होंगे।

बंगाल में 25,753 शिक्षकों की बर्खास्तगी का आदेश बरकरार

एससी बोला- सिलेक्शन प्रोसेस गलत

नई दिल्ली, एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर नए सिरे से चयन प्रक्रिया 3 महीने में पूरा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। पश्चिम बंगाल में स्स्ट्रे ने 2016 में 25 हजार शिक्षकों और गैर-शिक्षकों को नियुक्ति की थी। हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए कर्मचारियों को बर्खास्त किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की जांच को सही माना और कहा कि पूरी प्रक्रिया में धोखाधड़ी की गई। इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई की। शीर्ष कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई थीं।

- **ममता बोलीं-** व्यक्तिगत तौर पर फैसला स्वीकार नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ देर बाद ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान आया। ममता ने कहा- वह व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करती हैं, लेकिन उनकी सरकार इसे लागू करेगी और चयन प्रक्रिया को फिर से दोहराएगी। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या विपक्षी भाजपा और सीपीएम चाहते हैं कि बंगाल की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाए। उन्होंने कहा, इस देश के नागरिक के रूप में, मेरे पास हर अधिकार है और मैं जजों के प्रति सम्मान के साथ इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती। मैं मानवीय दृष्टिकोण से अपनी राय व्यक्त कर रही हूं। गलत सूचना न दें या भ्रम पैदा न करें। सरकार फैसले को स्वीकार करती है।
- **भाजपा बोली-** भ्रष्टाचार की पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राज्य भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने एक्स पर पोस्ट कर कहा - शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की पूरी जिम्मेदारी राज्य की विफल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ममता बनर्जी के शासन में कैसे पश्चिम बंगाल में शिक्षित बेरोजगार युवाओं की योग्यता को पैसे के बदले बेचा गया।

सुप्रीम कोर्ट के जज संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करेंगे

नई दिल्ली, एजेंसी

ज्यूडिशियरी में ट्रांसपेरेंसी और जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने पदभार ग्रहण करने के दौरान ही अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने का फैसला किया है। 1 अप्रैल को हुई फुल कोर्ट मीटिंग में सभी 34 जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की मौजूदगी में अपनी संपत्ति का खुलासा करने का फैसला लिया है। जजों ने यह भी कहा कि संपत्तियों से जुड़ी डिटेल सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। हालांकि वेबसाइट पर संपत्ति की घोषणा स्वैच्छिक होगी। सुप्रीम कोर्ट में जजों की निर्धारित संख्या 34 है। फिलहाल यहां 33 जज हैं, एक पद खाली है। इनमें से 30 जजों ने अपनी संपत्ति का घोषणा-पत्र कोर्ट में दे दिया है। हालांकि इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने के विवाद के बाद लिया गया है। जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में 14 मार्च को आग लगी थी। फायर सर्विस टीम को वहां अधजले नोट मिले थे। 1997 का प्रस्ताव- 1997 में, तत्कालीन CJI जे एस वर्मा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें जजों से अपेक्षा की गई कि वे अपनी संपत्ति की घोषणा चीफ जस्टिस को करें। हालांकि यह घोषणा सार्वजनिक नहीं की जानी थी। 2009 का न्यायाधीश संपत्ति विधेयक- 2009 में, न्यायाधीश संपत्ति और देनदारियों की घोषणा विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया।

वक्फ बिल पर राज्यसभा में खूब हुआ हंगामा

नड्डा बोले- विपक्ष राम मंदिर, कुंभ, बिहार इलेक्शन पर बोल रहा, ये सब चर्चा को डिरेल करने की कोशिश

नई दिल्ली, एजेंसी

वक्फ संशोधन बिल बुधवार को लोकसभा में पास होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया। दोपहर 1 बजे से चर्चा हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वक्फ बिल पर विपक्ष के रुख को लेकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा- हमने कांग्रेस नेतृत्व वाली UPA सरकार की तुलना में वक्फ बिल को लेकर कहीं ज्यादा गंभीरता दिखाई। यह बिल पार्टी इंट्रेस्ट का नहीं है, यह नेशनल इंट्रेस्ट का विषय है। इसलिए मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। विषय को डिरेल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा- बिल में कहीं राम मंदिर आ रहा है। कहीं कुंभ मेला दिख रहा है। बिहार का इलेक्शन दिख रहा। कहीं एअर इंडिया बिक गया। कहीं केरला का सिनेमा आ गया। ये सब चर्चा को डिरेल करने की कोशिश है।

रिजिजू बोले- बिल में ट्रांसपैरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी केंद्रित बदलाव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि व्यापक चर्चा के बाद तैयार किए गए बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया था। वक्फ को लेकर जेपीसी ने जितना काम किया, उतना काम किसी कमेटी ने नहीं किया। इससे पहले बुधवार देर रात तक चर्चा के बाद इस बिल को लोकसभा से पारित कर दिया गया। रिजिजू ने राज्यसभा में कहा- संशोधित बिल में मुसलमानों के धार्मिक क्रियाकलापों में किसी तरह का हस्तक्षेप कोई गैर मुस्लिम नहीं करेगा। हमने ट्रांसपैरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी पर केंद्रित बदलाव किए हैं। हम किसी की धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। गरीब मुसलमानों को न्याय मिले, हमारा यही उद्देश्य है।

लोकसभा से बिल पास

इससे पहले लोकसभा में बुधवार को 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। रात 2 बजे हुई वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया। 288 ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट डाले। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे उम्मीद (यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट) नाम दिया है। चर्चा के दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल फाड़ दिया। उन्होंने कहा- इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूं। बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है।

खड़गे ने कहा- मेरे पास वक्फ की एक इंच जमीन नहीं

इससे पहले राज्यसभा में सुबह भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर बुधवार को दिए बयान पर विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया। दरअसल, ठाकुर ने कहा था कि कर्नाटक में वक्फ की जमीन का भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी शामिल हैं। इस पर खड़गे ने कहा- आरोप सिद्ध करें या इस्तीफा दें। खड़गे ने कहा- अनुराग ठाकुर उनके या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के वक्फ बोर्ड की 1 इंच भी जमीन पर कब्जे को साबित कर देते हैं, तो मैं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगा।

राहुल बोले-चीन ने हमारी चार हजार वर्ग किमी जमीन कब्जाई

नई दिल्ली, एजेंसी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को भारत-चीन के राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह के जश्न को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा- चीन हमारे 4 हजार वर्ग किमी इलाके पर कब्जा करके बैठा है, लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारे विदेश सचिव (विक्रम मिस्री) चीनी राजदूत के साथ केक काट रहे थे। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान राहुल ने कहा- हम सामान्य स्थिति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपनी जमीन वापस मिलनी चाहिए। मुझे पता चला कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने चीनी राजदूत को चिट्ठी लिखी है और यह भी हमें दूसरों से पता चल रहा है। चीनी राजदूत भारत के लोगों को बता रहे हैं कि उन्हें चिट्ठी लिखी गई। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बीती 1 अप्रैल को भारत-चीन संबंधों के 75 साल पूरे होने पर भारत में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। उन्होंने चीन के राजदूत शू फेइहोंग के साथ काटा था। फेइहोंग ने ङ्क पर कार्यक्रम की तस्वीरें शेयर की थीं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बीती 1 अप्रैल को भारत-चीन संबंधों के 75 साल पूरे होने पर भारत में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। उन्होंने चीन के राजदूत शू फेइहोंग के साथ काटा था। फेइहोंग ने ङ्क पर कार्यक्रम की तस्वीरें शेयर की थीं। राहुल बोले- भाजपा की फिलॉस्फी हर विदेशी के सामने सिर झुकाना मोदी सरकार की विदेश नीति पर राहुल गांधी ने कहा- एक तरफ आपने चीन को हमारी जमीन दे दी और दूसरी तरफ अमेरिका ने हम पर टैरिफ (जैसे को तैसा टैक्स) लगा दिया।